यूपी नये भारत का 'ग्रोथ इंजन'

वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के साथ उत्तर प्रदेश में नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति से कानून का राज और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण सृजित हुआ। बुनियादी सुविधाएं हों या निवेश, हर दिशा में सरकार ने बड़ी लकीर खींची है। वर्ष 2018 में आयोजित 'यूपी इन्वेस्टर्स समिट' में 4.68 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। बेहतर क्रियान्वयन के चलते इनमें से 3.80 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। अब 'यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023' का आयोजन किया जा रहा है, इसके जरिये 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। निवेशकों के उत्साह को इसी से समझा जा सकता है कि जी.आई.एस. से पूर्व ही 1.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1.25 लाख करोड़ रुपये के 148 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित भी हो चुके हैं।

• 25 इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी • सिंगल विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र' के माध्यम से 355 ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT
New India's Growth Engine

> आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रदत्त सिद्धांत 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के अनुगमन से उत्तर प्रदेश का 'कायाकल्प' हो रहा है। अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीव्र कनेक्टिविटी और अन्य विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस यूपी अन्य राज्यों के लिए मॉडल प्रदेश बन गया है
>
> **योगी आदित्यनाथ**
> मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

10 लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य | **1.68 लाख करोड़ रुपये** के निवेश प्रस्ताव अभी तक प्राप्त | **1.25 लाख करोड़ रुपये** के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित

ज्वाला अग्निहोत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन की कड़ी में उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को फलीभूत करने की कड़ी में फरवरी 2023 में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। यह समिट वैश्विक औद्योगिक जगत को आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगा। समिट में भागीदारी करने के लिए अब तक लगभग 21 देशों ने रुचि दिखाई है। इनमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता करेंगे। इसके अलावा, दुनिया भर के औद्योगिक निवेशकों को समिट में आमंत्रित करने के लिए 17 राष्ट्रों व देश के 07 प्रमुख नगरों में रोड-शो भी आयोजित किये जायेंगे।

विश्वस्तरीय सुविधाएं

पिछले साढ़े पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में सक्षम नीतिगत समर्थन एवं विश्व-स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाकर कारोबारी माहौल में बड़े पैमाने पर सुधार किया गया है। 'प्रोएक्टिव इनवेस्टर कनेक्ट' तथा 'हैंडहोल्डिंग' के लिए राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने एवं उनके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए "निवेश सारथी" नामक एक नई ऑनलाइन प्रणाली (ऐप) विकसित की है, साथ ही एक ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम भी विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी/आईटीईएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीतियां तैयार करके औद्योगिक विकास के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं।

47 बड़ी कंपनियां आगे आयीं

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में विदेश की 47 बड़ी कंपनियों ने 24 सेक्टर में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। इनमें गूगल, अडोबी, सैमसंग, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, आईटीसी और जेबीएम ग्रुप जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं।